भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3163

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

सार्वजनिक परिवहन के लिए अवसंरचना विकास

3163. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के बड़े महानगरों, टीयर-3 और टीयर-2 श्रेणी के शहरों में वाहनों की निरंतर वृद्धि के कारण यातायात जाम की तेजी से बढ़ती समस्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति या समन्वित योजना तैयार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में सार्वजनिक परिवहन के अवसंरचना विकास के लिए नई योजनाएं लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) सरकार यातायात जाम को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चोक पॉइंट्स को कम करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों/नागरी केंद्रों और राज्य राजधानियों में विकास के लिए रिंग रोड, बाइपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के प्रस्तावों को स्वीकृति और अनुमोदन देती है। यातायात घनत्व, स्पीड ड्रॉप, शहर में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाली सड़क की संख्या, सड़कों की स्थिति और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

(ग) से (घ) शहरी परिवहन शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, जो एक राज्य का विषय है। इस प्रकार, प्रदूषण को कम करने के लिए पहलें, सड़क पर बढ़ती यातायात भीड़ को कम करने के लिए उठाए गए कदम संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए जाते हैं। सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी परिवहन मामलों के लिए केंद्रीय मंत्रालय होने के नाते शहरों/नगरीय स्थानीय निकायों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए विभिन्न मार्गदर्शक दस्तावेजों को अधिसूचित करते है। नीतिगत पहलों के अलावा, वर्तमान में देश के 25 शहरों में लगभग 1083 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क (55 किलोमीटर आरआरटीएस सहित) चालू हैं। दिल्ली और एनसीआर में लगभग 395.817 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के साथ शहरी क्षेत्रों में बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त, 2023 को पीएम-ईबस सेवा योजना शुरू की गई थी। अब तक 10,000 बसों में से सरकार ने पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 9,360 बसों को मंजूरी दी है।

****